श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न से मैं सहमत हूं। राज्यों सरकारों को राज्य विद्युत बोडों को जो सहायता करनी चाहिए थी उस के कारण फंडस रिलीज़ न करने के अलग-अलग हो सकते है। लेकिन ये वास्तविक कारण है जिनके लिए वर्ल्ड बैंक ने जो 350 मिलियन डॉलर्रस का ऋण उड़ीसा के लिए सेंक्शन किया था उस का यूटिलाइज़ेशन न होने के कारण उसे 250 मिलियन डॉलर दिया गया है। सभापति महोदय, यह जो 250 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है , वह भी अभी तक ययूटिलाइज़ नही हुआ है जब कि इस का पीरियड 2004 तक का है। सिर्फ 170 मिलियन डॉलर का यूटिलाइजेशन हो पाया है और अभी भी 85 मिलियन डॉलर यूटिलाइज नहीं किए हैं , यह वास्वतिकता है।

SHRI B. J. PANDA : My question is: Whether the State Government has asked for any help or any assistance in repaying this loan and whether the Cent Government will consider giving that assistance ?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति महोदय, इस प्रकार की कोई मांग राज्य सरकार से नहीं हैं ,लेकिन वर्ल्ड बैंक के द्वारा मंजूर किया हुआ ऋण जो कम किया गया था , उस के लिए जो सहायता मांगी गयी थी , वह सहायता दी गयी है। यूटिलाइजैशन कम होने के कारण् 50 मिलियन डॉलर पिछले वर्ष कम करने का प्रस्ताव वर्ल्ड बैंक में था , लेकिन केन्द्र सरकार की मध्यस्थता से 50 मिलिसन डालॅर की बजाय 35 मिलियन डॉलर कम हूआ था और 15 मिलियन डॉलर अतिरिक्त ऋण उड़ीसा सरकार को मिल पाया है।

Survey of Christians in Gujarat

*649. SHRI RAJU PARMAR:
SHRI BHAGAT RAM MANHAR :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that All India Christian Council have condemned the Gujarat Government's move to conduct a survey of Christians living in the State;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action proposed to be taken by the Central Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I. D. SWAMI): (a) to (c): A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The State Government of Gujarat has informed that no survey or census of any particular community in the State has been ordered by them.

---

† The qustion was actually asked on the floor at the House by Shri Raju Parmar

The All India Christian Council has, however, filed a Special Civil Application in the Gujarat High Court in this regard which is pending in the High Court of Gujarat at Ahmedabad.

श्री राजू परमार: चैयरमेन सर, स्टेट गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया है कि ऐसा कोई सर्वे क्रिश्चियंस के संबध में नही हो रहा है, यह बिल्कुल गलत बात है । यह हाऊस को मिस-इंफॉर्म किया जा रहा है । गुजरात गवर्नमेंट ने अभी तक तीन बार ऐसा सेर्व करने की कोशिश की है । पहली बार वर्ष 1991 में ऐसा सर्वे कराने की कोशिश की गयी थी जिस को हाई कोर्ट ने बंद करवाया था । दूसरी बार ,2001 में भी क्रिश्चियंस का ऐसा सर्वे कराने की कोशिश गुजरात गवर्नमेंट ने की थी और अभी तीसरी बार वर्ष 2003 में भी यह सर्वे कराने की बात चल रही है । मैं आपकी जानकारी और पूरे हाऊस की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी स्टेंट के स्टेट होम मिनिस्टर ने पब्लिकली कबूल किया है कि ऐसा सर्वे हो रहा है । उसमें उन्होनें जो कारण बताया , वह यह कि लोक सभा के सांसद राम विलास पासवान जी ने ऐसा एक क्वैश्चन किया है कि गुजरात में कितने लोगों को क्रिश्चयन में कन्वर्ट किया गया है और उसके जवाब में ऐसा सर्वे हम लोग कर रहे हैं । क्या यह जानकारी हमारे आदरणीय मंत्री महोदय को नही है ? उस हाऊस में पासवान जी ने इस इश्यू को रेज किया और कहा कि मैंने ऐसा कोई क्वैश्यचन पूछा ही नही है और इसके लिए वे प्रिवीलेज मोशन लाए तो स्पीकर साहब ने वह प्रिवीलेज मोशन गुजरात के स्पीकर को रेफर किया । क्या यह जानकारी हमारे होम मिनिस्टर साहब को नहीं है ? इसके बारे में क्या माननीय मंत्री जी बताऐंगे ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सभापति जी, यह बात सही है कि वर्ष 1999 में भी यह सवाल उठा था और वर्ष 1999 में क्रिश्चियन आर्गेनाइजेशन की तरफ से एक पिटीशन कोर्ट में फाइल की गई थी। तो उस वक्त एकऑर्डर जो डी.जी.ने वहां जारी किया था, उसको विदड्रा कर लिया गया था और पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गई थी । उसके बाद दूबारा जब एडमिनिस्ट्रेटिव जो 184 का नोटिस था, उसकी वजह सेजो कनवर्शन के खिलाफ एक लॉ बनाना चाहता थे उसके सिलसिले में जब इन्फोरमेशन मांगी गई तो तमाम एस.पीज़. को विद-इनू-डेजट-च्टिठी गई । उस लिससिले में जब किसी थाने में एक दो जगह जाकर पूछा गया तो उस समय इस क्रिश्चियन आर्गेनाइजैशन ने हाई कोर्ट में फिर पिटिशान की । हाई कोर्ट में उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई । इसमे हाई कोर्ट ने यह ओब्जर्व किया कि स्टेट गवर्नमेट को यह अथोरिटी है कि एडमिनिस्ट्रेटीव लोकल इन्क्वायरी के सिलसिले मे , इंटरोगेशन के सिलसिले में कोई इंफोरमेशन कलेक्ट करने के सिलासिले मे जो भी इंफोरमेशन लेना चाहे वह ले सकती है और इसलिए वह पिटिशन डिसमिस हो गई थी । जो सवाल आया है कि इस तरह से लोकल इंक्वायरी किसी थाने में की गई और उन्होंने बार-बार यह कहा कि हमने कहीं सर्वे कराया है ,तो कभी सर्वे नहीं करया , सर्वे का कोई ऑर्डर नहीं है । अब तो वे हाई कोर्ट में चले गए है , That Christian Organisation has already gone to the High Court और हाई कोर्ट ने जून में उसकी पेशों रखी हुई है । गुजरात ने अपना एफीवेडेविट फाइल कर दिया है । यह एफीडेवटि भी इन्हीं लाइन्स पर है कि हमने कभी कोई सर्वे नही कराया । वैसे

the information of the House, through you, I may say, कि यह मामला थोड़ा सा सेंसटिव हो जाता है , लेकिन रिलिजियन के बेसिस पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया डिसेनियल सेंसस होती है , हर घर में जाकर इंफोरमेंशन रिलिजियन के बारे में ली जात है और उसकी किताब छपवाई जाती है ।

श्री राजू परमार : प्रिवीलेज मोशन के बारे में आपने नहीं बताया ।

श्री सभापति : दूसरे हाऊस का कैसे बता सकते हैं ?

श्री राजू परमार: सर, प्रिवीलेज मोशन लाया गया है ।....(व्यवधान) ...

श्री सभापति : किस हाऊस में लाया गया है ?...(व्यवधान)...

श्री राजू परमार : सर, वैसे सर्वे नहीं हो रहा , यह बात सही है, लेकिन वहां के मिनिस्टर ने खुद कबूल किया है । ....(व्यवधान)...

श्री सभापति : नही,नहीं । .अगर दूसरा क्वैश्चन आपको करना हो तो कर लीजिए ।

श्री राजू परमान : सर, सेकेण्ड सप्लीमेंटरी पूछना है । आज गुजरात में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस है और उनके साथ जुड़े हुए संगठन बजरंग दल, वीएचपी , यह सब है । गुजरात के अंदर इन संगठनों के जरिए जो लिटरेचर बांटा जाता है , जो पत्रिकाएं बांटी जाती है , उसमें कहा जाता है कि पहले माइनोरिटी का सफाया किया जाए । क्रिश्चियन का सफाया किया जाए और

श्री सभापति : नहीं सफाया नहीं । इस क्वैश्चन में तो सेंसस का मामला हैं ।

श्री राजू परमार : और बाद में दलितों का सफाया किया जाए । ...(व्यवधान) ...

क्या ऐसा डाटा कलेक्ट करके उनको दे दिया जाएगा । जिस तरह अभी गुजरात में .राइटस हुए हैं उसमें माइनोरिटी को चुन-चुन कर उनके घर जलाए गए, चुन-चुन कर उनकी दुकानें जलाई गई , क्या ऐसी बात क्रिश्चियनों के साथ भी की जाएगी ?...(व्यवधान)...

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बैठिए ।

SHRI JANARDHANA POOJARY : This is not fair, *(Interruptions)* Why arc you getting up ? *(Interruptions)*

श्री सभापति : पुजारी जी, आप बैठिए ...(व्यवधान) आप इस क्वैश्चन को कहां ले गए । आप खुद ही विचार ही करें कि इस क्वैश्चन की परिधि में यह आता है क्या ? क्वैश्चन है सेंसस का और आप ले जाते हैं दूसरे मामलों में ।

श्री राजू परमार : नहीं ,नहीं ,सर, यह हो रहा है । ....(व्यवधान)..

श्री सभापति : आप देखिए , इस क्वैश्चन को । ...(व्यवधान)... इस क्वैश्चन में कहां से गुजरात का दंगा आ गाया ....(व्यवधान)

श्री भगत राम मनहर : सभापति महोदय, सर्वे करना और इन्फोरमेशन कलेक्ट करना दो अलग-अलग बातें है । किसी भी जाति , धर्म आदि के सर्वेक्षण और उनकी जनगणना का अधिकार किसी भी देश में सेंसस विभाग **को** है । गुजरात सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग किया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गुजरात में ईसाईयों का सर्वेक्षण कराने का क्या मकसद है ? इस प्रकार के सर्वे अनैतिक एवं **गैर**-कानुनी है । इस कार्रवाई पर विराम लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने गुजरात सरकार के विरूद्ध क्या कार्रवाई की है ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सर, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि गुजरात गवर्नमेंट ने कोई सर्वे किया ही नही है । कोई एडमिनिस्ट्रटिव लोकल इंक्वायरी अगर कहीं की है तो उसका जवाब आ चुका है ।

प्रो0 अलका क्षत्रिय : धन्यवाद सभापति जी ।

सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने **अभी** बताया है कि ऐसा कोई सर्वेक्षण नही किया गया ,लेकिन इंटेलिजंस ब्यूरो सरकार का ही एक हिस्सा है और अभी हाल ही मे इंटेजिजेंस ब्यूरो ने एक प्रोफार्मा सभी एसपीज़ को भेजा था । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि उस प्रोफार्मा की विगत क्या है ? प्राफार्मा में क्या –क्या मांगा गया था सर्वे के अंदर और क्या मंत्री जी कबूल करते हैं कि ऐसा कोई प्रोफार्मा भेजा गया था ? अगर मंत्री जी मानते है कि प्रोफार्मा भेजा गया था तो मैं कहना चाहती हूं कि मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं इंटेलिजंस ब्यूरो ने हर जगह यह प्रोफार्मा भेजा है ।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सभापति जी, सैंट्रल गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी है, उसकी तरफ से गुजरात गवर्नमेट को या किसी एसपी को कोई प्रोफार्मा नहीं भेजा गया । अगर वहां की सीआईडी ने कोई प्रोफार्मा कोई इन्फारमेशन लोकल लैवल पर एसपी को भेजी थी तो उसके बारे में मैने जबाव दिया है कि यह एसपी से कोई इन्फारमेशन कलेक्ट करने के लिए थी क्योकि वे एंटी कन्वर्जन बिल पास करना चाहते थे । उस वक्त वह इंक्वायरी की थी और सब एसपी से, सिर्फ एक जगह ही नही बल्कि गुजरात में सभी एसजीज़ से पूछा गया था क्योंकि 6 स्टेटस ने आलरेडी एंटी कन्वर्ज़न एक्ट बना रखा है , वे भी बनाना चाहते थे । उस सिलसिले में जो इंक्वायरी की गई थी उस पर भी क्रिश्चिएन आरगेनाइजेशन की तरफ से हाई कोर्ट में एक पेटीशन दाखिल की गई थी । वह पेटीशन डिसमिस्ड हुई और उसमें ओब्जर्वेशन हुई कि सरकार को पूरा अख्तियार है इस तरह कही इन्फोरमेशन कलेक्ट करने का ।

प्रो0 अलका क्षत्रिय : सर, मैं जानना चाहती हूं कि इस तरह का कोई प्रोफार्मा भेजा गया था या नहीं ? अगर भेजा गया था तो मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री सभापति : आप बैठिये । अब कौन गुमराह कर रहा है,पता ही नहीं लग रहा ।

श्री सुरेश पचौरी : सर, मैं आपके ज़रिए विनम्रतापुर्वक यह जानना चाहता हूं कि कौन से गृहमंत्री जी सत्य बोल रहे हैं ? जिन गृह मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है उन्होने कहा है कि .....

श्री सभापति : कहां उत्तर दिया है ?

श्री सुरेश पचौरी : सर, मैं उसी प्वाइंट पर कह रहा हूं कि यह गलत जानकारी दी गई है।

श्री सभापति : कहां उत्तर दिया है – लोक सभा में या राज्य सभा में ?

श्री सुरेश पचौरी : सर, राज्य सभा में दिया है। आज का जो प्रश्न संख्या 649 है , उसमें जो स्टेटमेंट है,उसमें यह है कि :

"The State Government of Gujarat has informed that no survey or census of any particular community in the State has been ordered by them."

माननीय गृह राज्य मंत्री , श्री ईश्वर दयाल स्वामी जी ने यह स्वीकार किया कि फरवरी ,1999 में एक सर्वे हुआ था , जिसका वहां के हाई कोर्ट ने काग्निजेंस लिया था और जो सीक्रेट सर्वे का सरकूलर था , फिर उसको निरस्त किया गया था। तो पहला प्रश्न तो यह उठता है कि यह स्टेटमेंट करेक्ट है या माननीय गृह राज्य मंत्री जी का वक्तव्य करेक्ट है ?

श्री सभापति : एक और पूछ लीजिएगा कि हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है या नहीं और वह कौन सा सही है।

श्री सुरेश पचौरी : वह तो इन्होनें स्वीकार किया है कि हाई कोर्ट ने काग्निजेंस लिया है। यह तो इन्होने स्वीकार किया है कि गुजरात हाई कोर्ट ने सुओ-मोटो काग्निजेंस लिया है सीक्रेट कंट्रोवर्शियल सरकुलर के मामले में। तो एक तो मेरा यह कहना है कि इस व्कतव्य के द्वारा जो जानकारी दी गई है वह गलत है।

दूसरे भाग के रूप में मेरा यह कहना है कि खुद मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि जो वहां गुजरात के मंत्री है , उन्होनें कूछ जानकारी चाही थी। उस जानकारी के चाहने पर वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में जो एक असुरक्षा का वातावरण हो गया है और उसकी वजह से जो उन्हें रिप्रजेंटेशन मिला है उस रिप्रजेंटशन की वजह से क्या यह सही है कि नेशनल कमीशन फार माइनांरिटज़ ने गुजरात सरकार को मार्च ,2003में इस संबंध मे एक नोटिस जारी किया है ? यदि नोटिस जारी किया हे तो उस नोटिस के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सर, पहली बात तो मै माननीय सदस्य को बता दूं कि मेरे जवाब में कोई कंट्राडिक्शन नही हैं , पहले भी मेरा यही जवाब था आज भी यही जवाब है 1मैने यह कहा था कि 1999 में जब एक सरकुलर जारी हूआ था, वह तुरंत विदड्रा कर लिया गया था। This is a fact कि सर्वे नहीं हूआ। मैंने यह कहा कि गुजरात गवर्नमेंट आज भी यह कह रही है कि सर्वे नहीं कराया गया। जब उस पर ऐतराज़ हुआ या एप्रिहेंशन हुई , उसी वक्त वह सरकुलर वापिस ले

लिया गया था । अब जब दूसरे सर्वे के बारे में कहा गया है, तो अभी भी यही जवाब है कि सर्वे नहीं कराया गया है ।

जहां तक माइनॉरिटी कमीशन के नोटिस का सवाल है तो That particular organisation has already gone to the High Court, and the High Court has fixed the case for 6th of June.

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 650.

श्री भारतेन्दू प्रकाश सिंहल : सर,मेरा नाम रह गया है ।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, आप तो यहां रहेगें न । प्रश्न संख्या 650 डा0 अबरार अहमद ।

डा0 अबरार अहमद : सभापति महोदय, मेरा दल श्री जॉर्ज फर्नीन्डीज को रक्षा मत्री के रूप में रिकोगनाइज़ नही करता है , इसलिए मैं सवाल नहीं पूछना चाहता हूं ।

श्री सुरेश पचौरी : सभापति महोदय, इस सबंध मे आपको कुछ करना चाहिए । हम लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं । आप हमारे संरक्षक हैं 1 हमारी प्राथर्ना है कि आप कुछ ऐसी पहल करें कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सददबुद्धि दें ।यह तो उनका prerogative है कि डिफेंस मिनिस्टर किसी और को बना दें ताकि डिफेंस जैसे इश्यू पर हम सवाल पूछ सकें 1आदरणीय उपप्रधानमंत्री जी ने भी ऐसी इच्छा व्यक्त की थी कि जल्दी ही इसका कोई समाधान निकालना चाहिए । आज वे यहां उपस्थिति है , यह हमारा अहोभाग्य है , मेरी प्रार्थना है ,कि वे भी इस सबंध में कुछ पहल करें...(व्यवधान)..

श्री सभापति : **द्यो**ड़िये ,छोडिये (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : महोदय , यह इतना सेंसिटिव इश्यु है (व्यवधान)

श्री सभापति : आप जो यह कह रहे है , वह सही है । लालू जी, मैं इस सबंध में इतना बता दूं कि बातचीत हो रही है ।

श्री लालु प्रसाद : ठीक है, जो आप फैसला करें ।

* 650 WITHDRAWN

*651 [The questioner (Shri K. Rama Mohan Rao) was absent. For answer *vide* page 44 *infra]*